

मैसर्स अनिता ट्रेडिंग कंपनी
रायसिंहनगर

...अपीलार्थी

बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-रायसिंहनगर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.एम. पेडीवाल

अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 94/आरवैट/हनुमानगढ़/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त रायसिंहनगर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2012 में आरोपित रिवर्स कर रुपये 8,77,854/- को यथावत रखा है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवं खल का निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों रूई, बिनौला तेल एवं खल बिनौला का व्यवहारी राज्य एवं अंतर्राज्यीय में विक्रय करता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने रॉ-कॉटन की स्थानीय खरीद पर शत-प्रतिशत इनपुट क्रेडिट का क्लेम किया। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के दौरान यह पाया कि व्यवहारी द्वारा कच्चे माल के रूप में बिनौला इत्यादि प्रयुक्त किया जाता है तथा निर्मित माल तेल व खल है जिसमें तेल कर योग्य माल के रूप में विक्रय किया जाता है तथा खल कर मुक्त माल के रूप में बेची जाती है। अधिनियम की

धारा 18 के प्रावधानों के अधीन कर योग्य माल के निर्माण के रूप में प्रयुक्त हुए कच्चे माल बिनौला की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का दावा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है जबकि फर्म द्वारा आनुपातिक रूप से खल निर्माण में प्रयुक्त बिनौला खरीदपर चुकाये गये वैट राशि का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। इस संबंध में व्यवहारी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यवहारी ने जवाब में कहा कि कर मुक्त माल खल मेन प्रोसेसिंग का बाई प्रोडक्ट है। आई.टी.सी. कच्चे माल की खरीद पर ली गई है जो विधिसम्मत है। सशक्त अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.02.2012 में यह ठहराया कि अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार व्यवहारी विनिर्मित माल कर योग्य एवं कर मुक्त पर अनुपात के आधार पर आई.टी.सी. ले सकता है। व्यवसाई की लेखा-पुस्तकों के अनुसार नरमा कपास की जिनिंग से प्राप्त बिनौला 21130 क्विंटल कीमत रुपये 2,95,82,000/- एवं कर चुकाकर खरीद किये गये बिनौला 1496.33 क्विंटल कीमत 22,10,475/- रुपये कुल कीमत 3,17,92,475/- रुपये का पिड़ाई में प्रयुक्त किया गया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से 12,71,699/- रुपये का आगत कर का समायोजन लिया गया है। व्यवसाई के निर्माण खाते के अनुसार कर योग्य माल का अनुपात 30.97 प्रतिशत एवं कर मुक्त माल का अनुपात 69.03 प्रतिशत है। अतः प्रयुक्त माल रुपये 3,17,92,475/- पर रुपये 12,71,699/- का आगत कर लिया है जो गलत है। विनिर्माण कर योग्य माल 30.97 प्रतिशत एवं कर मुक्त माल खल बिनौला 69.03 प्रतिशत पर अनुपातिक रूप से कर मुक्त माल खल बिनौला के निर्माण में प्रयुक्त माल की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि का टैक्स रिवर्स कर आई.टी.सी. लेना था। विनिर्मित कर योग्य माल तेल व कर मुक्त खल में अनुपात 30.97 प्रतिशत एवं 69.03 प्रतिशत है। अतः कुल आई.टी.सी. रुपये 12,71,699/- का 69.03 प्रतिशत से रुपये 8,77,854/- रिवर्स टैक्स निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेश दिनांक 15.02.2012 के विरुद्ध व्यवसाई द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर के समक्ष अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2013 द्वारा अपील इस आधार पर अस्वीकार की गई है कि इसके तथ्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा मै. दुर्गेश्वरी फूड्स प्रा. लि. के प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.12.2011 के समान है जिसमें यह ठहराया गया है कि आगत कर का समायोजन कर योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के अनुसार ही स्वीकार्य है, कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए नहीं। अपीलीय अधिकारी के



लगातार.....3

उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध व्यवसाई द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से श्री एस. एम. पेडीवाल ने उपस्थित होकर बहस करते हुए बताया कि व्यवहारी द्वारा रॉ कॉटन व कॉटन सीड कर योग्य माल कॉटन व कॉटन सीड ऑयल उत्पादन के लिए क्रय किया गया है। व्यवहारी ने कॉटन सीड क्रय नहीं किया है बल्कि रॉ कॉटन की जिनिंग के दौरान प्राप्त किया है जिस पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने जिस राशि पर रिवर्स टैक्स लगाया है उसकी गणना सही नहीं है जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत लेखों से स्पष्ट होती है। खल बिनौला बाई प्रोडक्ट है जिसके रॉ मैटेरियल पर चुकाया गया आगत कर समायोजन योग्य होना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर रिवर्स किये गये इनपुट टैक्स का समायोजन दिया जावे। इन्होंने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47/2014 में स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकरण के समान है व इस प्रकार प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर विचाराधीन है कि माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chemicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06.11.2008 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CTO(A-E) Sri Ganganagar V/s Ms. Durgeshwari Food Ltd. Sri Ganganagar S.B. Civil Sel Tax Revision Petition No. 193-194/2009 निर्णय दिनांक 08.12.2011 पारित करते समय ध्यान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हुआ है तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आधार पर कर मुक्त माल के अनुपात में इनपुट टैक्स रिवर्स किया जाना न्यायोचित नहीं है।
5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समानान्तर प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्री गंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स

27/

लगातार.....4

दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वैट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल रॉ कॉटन व कॉटन सीडस से निर्मित कर मुक्त माल बिनौला खल की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में रॉ कॉटन व कॉटन सीडस की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल बिनौला खल की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी का भी अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे। उक्त कथन के साथ उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के व्यवहारियों से वैट चुकाकर खरीद किये गये रॉ कॉटन व कॉटन सीडस का उपयोग बिनौला, बिनौला तेल एवं बिनौला खल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया है, जिसमें बिनौला खल कर मुक्त उत्पाद है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से कच्चे माल के रूप में वैट चुकाकर खरीदे गये उक्त रॉ कॉटन व कॉटन सीडस के मूल्य पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर विचारण के पश्चात वैट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के आलोक में विक्रय किये गये कर योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय होने एवं कर मुक्त बिक्रीत माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देय नहीं होना मानते हुए इस पर रिवर्स टैक्स एवं ब्याज का आरोपण किया गया है।

8. इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2009 के विरुद्ध विभाग की

2m✓

ओर से प्रस्तुत की गई एस. बी. सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2012 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20 व 21 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely "Aata", "Maida" and "Suji" manufactured out of raw material (Wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same can not be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

9. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से इस बात की पुष्टि होती है कि आगत कर का समायोजन कर योग्य माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के अनुसार ही स्वीकार्य है, कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए नहीं। यदि क्रय किये गये कच्चे माल का प्रयोग कर योग्य एवं कर मुक्त माल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है तब कर योग्य उत्पादित माल के अनुपात में ही आगत कर का समायोजन देय होगा।

10. जहां तक विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय अभी अंतिम नहीं है क्योंकि यह निर्णय पारित किये जाते समय माननीय अपैक्स कोर्ट का Commissioner of Central Excise, Mumbai V/s Ms National Organic Chemicals Civil Appeals No. 1130/2003 निर्णय दिनांक 06.11.2008 प्रस्तुत नहीं किया था जिसके आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल (वैट) रिवीजन पिटिशन नंबर 47/2014 विचाराधीन है, इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पारित हो जाने के पश्चात उस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य चस्प होने पर तदनुरूप

2m

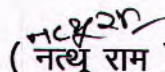
निर्णय किया जाना विधिसम्मत है। यदि माननीय उच्च न्यायालय ने या अन्य माननीय अपेक्स कोर्ट में कोई प्रकरण विचाराधीन है जिसके तथ्य समान हैं तो निर्णय उपरांत तदनुसार धारा 26 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

11. अपीलार्थी का अपील में यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने जिस राशि पर रिवर्स टैक्स लगाया है उसकी गणना सही नहीं है जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत लेखों से स्पष्ट होती है। अपीलार्थी ने न तो अपील में यह स्पष्ट किया है कि गणना किस प्रकार सही नहीं है व न ही बहस के समय इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट की है जिससे यह बिंदु भी स्वीकार योग्य नहीं है।

12. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में कर मुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार किये जाने को विधिसम्मत ठहराया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिनौला खल की बिक्री के अनुपात में आरोपित रिवर्स टैक्स को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

13. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थू राम)
सदस्य